लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 382

02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र पार्क की स्थापना

382. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान) योजना के अंतर्गत केरल सरकार से एक वस्त्र पार्क की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश में स्थापित प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत अब तक आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है;

(घ) पीएम मित्र पार्कों के कार्यान्वयन में शामिल निजी कंपनियों या उद्योग भागीदारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत ऐसी निजी संस्थाओं द्वारा कुल कितनी धनराशि या निवेश का योगदान दिया गया है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्र क्षेत्र को मजबूती से स्थापित करने की दृष्टि से, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्लग और प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है।

मंत्रालय को मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 13 राज्यों से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए तमिलनाडु (वीरुधनगर) सहित 7 साइटों को अंतिम रूप दिया है। अन्य चयनित साइट तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) हैं।

केरल सरकार से पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ग): अब तक पीएम मित्र पार्क योजना के तहत तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र अर्थात् इन 4 पीएम मित्र पार्कों को विकास पूंजी सहायता (डीसीएस) के रूप में कुल 160 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ): प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र निर्माताओं ने पीएममित्र पार्कों में रुचि दिखाई है। अब तक पीएम मित्र योजना के तहत प्राप्त/स्थापित निवेश/हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य**	**निवेश (समझौता ज्ञापन और आशय पत्र) (करोड़ रुपए में)**
1	मध्य प्रदेश	14,099
2	गुजरात	13,084
3	उत्तर प्रदेश	5270
4	तेलंगाना	3862
5	महाराष्ट्र	3245
6	कर्नाटक	1700
7	तमिलनाडु	1231
	कुल	42,491

***